VOL- VII ISSUE- X OCTOBER 2020 PEER REVIEW e-JOURNAL IMPACT FACTOR 6.293 ISSN 2349-638x

भारत में बेरोजगारी का समस्या

डॉ0 पार्थसारथी पाण्डेय

अर्थशास्त्र- विभाग

का०सु० साकेत पी०जी० कॉलेज अयोध्या, फैजाबाद उ०प्र०

ईमेल:- drps.pan@gmail.com

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में जिन महत्वपूर्ण समस्याओं से ग्रस्त है, उनमें बेरोजगारी सर्वाधिक चिंता का विषय है। बिडम्बना यह है कि प्रायोगिक दृष्टि से योग्य व्यक्ति लोग काम करना चाहते हैं; किन्तु उन्हें काम नहीं मिल पाता। श्रम शक्ति या मानवीय पूँजी का सर्वोत्तम उपयोग न होना हमारी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का द्योतक है। बेरोजगारी, निर्धनता और पिछड़ेपन का दुष्चक्र आज भी निरन्तर चल रहा है। इस दुष्वक्र पर नियंत्रण प्राप्त किये बिना देश की आर्थिक प्रगति सम्भव नहीं प्रतीत होती। यह दुर्भाग्य ही रहा है कि समाज में रोजगार के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा की तुलना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई। देश में बढ़ते औद्योगीकरण का नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि कृषि को उत्तम मानने वाला भारतीय, गाँव छोड़कर शहर में अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य न मिलने के बावजूद नौकरी के लिए लम्बी-लम्बी कतारों में आ खड़ा हुआ है। नौकरी करना उसके लिए गर्व की बात बन गयी है। इस प्रकार नौकरी के प्रति बढ़ते आकर्षण ने बेरोजगारी विशेषतौर पर शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और विकराल बना दिया है । .

भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। देश जनसंख्या विस्फोट अर्थात अति जनसंख्या की अवस्था से गुजर रहा है। यदि बेरोजगारी के क्षेत्र में भी यही स्थिति कही जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।! वर्तुान समय एवं सन्दर्भो में बेरोजगारी की समस्या एक स्थायी और दुःसाध्य समस्या का रूप धारण कर चुकी है जबकि भारतीय आयोजन रणनीति में विभिन्न योजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों में से एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी दूर करना और पूर्ण रोजगार उपलब्ध करना रहा है। डॉ० ए० के० सेन के अनुसार- "भारत में बेरोजगारी एक-ऐसी जूटिल समस्या है |

जिसके सम्बन्ध में जितना लिखा गया है उतना संसार के किसी अन्य विषय पर नहीं लिखा गया।[2]

सामान्यतः किसी भी देश की पूरी श्रमिक संख्या रोजगार में संलग्न नहीं होती, अपितु उसका कम अथवा अधिक भाग बेरोजगार होता है। बेरोजगारी की यह मात्रा अल्पविकसित देशों में सामान्यतया अधिक होती है, विशेष रूप से ऐसे देशों में जहाँ जनसंख्या आधिक्य की स्थिति विद्यमान है और वह निरन्तर बढ़ रही है। भारत के सन्दर्भ में भी यह तथ्य अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। निःसन्देह बेरोजगारी भारत की मूलभूत एवं गम्भीर समस्या है। इसका विस्तार देश में व्यापक स्तर पर है।

अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र इससे मुक्त नहीं है। बेरोजगारी की व्यापकता न केवल ग्रामीण और शहरी हिस्सों में है बल्कि देश का शिक्षित और अशिक्षित तथा कामगार वर्ग भी बड़ी संख्या में बेरोजगार है।

समेकित रूप से देखने पर स्पष्ट होता है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति अयावह है। देश के विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी की दरों में काफी भिन्नता दिखाई देती है। तालिका 2.1 में बेरोजगारी की इन दरों का व्यापक विश्लेषण किया गया है।

तालिका 2.1

प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी दरें

क्रम	राज्य	बेरोजगारी दर – (श्रम शक्ति प्रतिशत)		
		1984-85	1993-94	1999-2000
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.35	6.67	7.94
2.	असम	5.09	7.96	8.00
3.	बिहार	4.04	6.25	7.35
4.	गुजरात	5.79	5.23	4.63
5.	हरियाणा	7.59	6.59	4.67
6.	हिमांचल प्रदेश	3.12	1.82	2.93
7.	कर्नाटक	5.06	4.89	4.61
8.	केरल	21.19	15.50	20.27
9.	मध्यप्रदेश	2.86	3.42	4.60
10.	महाराष्ट्र	4.67	4.97	7.09
11.	उड़ीसा	6.44	7.28	7.38
12.	पंजाब	5.04	3.08	4.15
13.	राजस्थान	5.74	1.33	3.06
14.	तमिलनाडु	10.36	11.44	12.05
15.	उत्तर प्रदेश	3.44	3.45	4.27
16.	पश्चिम बंगाल	8.13	9.87	14.95
17.	दिल्ली	4.77	1.91	4.58
सम्पूर्ण भारत		6.09	6.03	7.32

स्रोत:- इण्डियन इकोनोमी सिन्स इंडिपेन्डेंस- उमा कपिला, 2002, पेज-835

तालिका 2.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बेरोजगारी दरें लगभग 3 प्रतिशत तमिलनाडु में 12 प्रतिशत और केरल में 21 प्रतिशत है | यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि ये अंतर्राजीय विचलन समय के सापेक्ष लगभग अपरिवर्तित रहे हैं | क्योकि इन्ही राज्यों में 1987-88 तथा 1999-2000 में भी बेरोजगारी दरें काफी ऊँची रही है |

किसी पूर्व अनुमानित परिकल्पना के आधार पर राज्यों की बेशैजगारी दरों में विचलनों एवं इसके विस्तार को सही तरह विवेचित नहीं किया जा सकता। ऐसे राज्य जहाँ-जहाँ पारिश्रमिक पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में अधिक हैं वहाँ श्रम-शक्ति का शोषण भी अधिक है तथा इसके विपरीत केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य भी है जहाँ सामाजिक सुरक्षा उपायों की उत्कृष्टता के बावजूद बेरोजगारी की दरें ऊँची हैं। उक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्यों की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के सापेक्ष, विशेषतया रोजगार के गुणात्मक पक्ष की पृष्ठभूमि में रोजगार सृजन की नये सिरे से समीक्षा आवश्यक हो जाती है।

देश में बेरोजगारी की स्थिति के ऑकलन हेतु दाँतवाला समिति की रिपोर्ट के आधार पर NSSO ने चार प्रमुख रोजगार एवं बेरोजगारी दरों की व्याख्या की है। इस आधार पर प्रथम वर्ग सामान्य मौलिक स्थिति UPS) के अन्तर्गत वे बेरोजगार आते है, जिन्हें वोग्यता के बावजूद वर्ष के 365 दिनों में अधिकांशतया रोजगार रहना पड़ा है। दूसरा वर्ग सामान्य मौलिक सहायक

स्थिति (UPSS) का है। इसके अन्तर्गत वर्ष के अधिकांश दिनों में कार्यकारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रोजगार प्राप्त कर लेता है या आर्थिक गतिविधियों में संत्रग्ण रहता है। चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति के अन्तर्गत क्रमशः सप्ताह के सात दिनों में एक दिन और बारह घंटे में कम से कम एक घंटें अवश्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहा हो या फिर रोजगार प्राप्त किया हो। इन चार वर्गों के आधार पर सम्पूर्ण भारत वर्ष में नगरीय और ग्रामीण बेरोजगारी की स्थिति तालिका 2.2 के आधार पर स्पष्ट है।

तालिका 2.2

बेरोजगारी दरें (वैकल्पिक पद्धतियों के आधार पर)

	सामान्य मौलिक स्थिति (U.P.S)	सामान्य मौलिक एवं सहायक स्थिति (U.P.S)	चालू साप्ताहिक स्थिति (U.P.S)	चालू दैनिक स्थिति (U.P.S)
ग्रामीण				
1977-78	3.26	1.54	3.74	7.70
1983	1.91	1.13	3.88	7.94
1987-88	3.07	1.98	4.19	5.25
1993-9	1.80	1.20	3.00	5.63
1999-200	1.96	1.43	3.91	7.21
नगरीय				
1977-78	8.77	7.01	7.86	10.34
1983	6.07	5.02	6.81	9.52
1987-88	6.56	5.32	7.12	9.36
1993-94	5.21	4.52	5.83	7.43
1999-2000	5.23	4.63	5.89	7.65
सम्पूर्ण भारत				
1977-78	4.23	2.47	4.48	8.18
1983	2.77	1.90	4.51	8.28
1987-88	3.77	2.62	4.80	6.09
1993-94	2.56	1.90	3.63	6.03
1999-2000	2.56	2.23	4.41	7.32

स्रोत -इण्डियन इकोनॉमी सिन्स इण्डिपेन्डेंस- उमा कपिला, 2002, पेज - 835.

तालिका के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न आधारों पर विश्लेषित बेरोजगारी दरों पर पर्याप्त भिन्नता है। सामान्य मौलिक एवं सहायक स्थिति((UPSS) बेरोजगारी दरों और चालू दैनिक स्थिति बेरोगारी दरों को आधार मानकर यदि सम्पूर्ण भारत वर्ष में बेरोजगारी की स्थिति का आंकलन किया जाये तो स्थितियाँ काफी विषम दिखाई पड़ती है। निःसंदिह यह चिंता को विषय है।

आज देश में बेरोजगारी के अनेक दुष्परिणाम सामनें आ रहे हैं जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए गम्भीर व घातक सिद्ध हो रहे हैं। व्यापक बेरोजगारी की दशा में राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा कम होती जा रही है, जिसका पूँजी-निर्माण, व्यापार-व्यवसाय और प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गरीबी इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में ऐसे कुशल श्रमिक भी होते है जिनके तकनीकी कौशल व प्रशिक्षण पर किया गया व्य निरर्थक अथवा बर्बाद हो जाता है। बेरोजगारी के आर्थिकेतर परिणाम अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के आभाव में बेरोजगार प्रायः अनेक बुराईयों के शिकार हो रहे हैं। उनके जीवन का कोई अर्थ व महत्व नहीं रह गया है। अतः लोगों के जीवन-स्तर की ऊपर उठानें तथा देश की बहुमुखी प्रगति और समृद्धि के ड्रिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान निः संदेह एक अपरिहार्य शर्त बन गयी है |.

सन्दर्भ सूची

1. शर्मा, सुनील कुमार; "भारत में बेरोजगारी की समस्या" , योजना-मार्च,1999,पृष्ठ संख्या, 31.
2. सेन, ए० के० एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, 1975

3. अग्रवाल, ए० एन०; "भारतीय अर्थव्यवस्था" 2002 पृष्ठ संख्या, 129.
4. कपिला, उमा; इण्डियन इकोनॉमी सिन्स इण्डिपेन्डेंस,2002, पृष्ठ संख्या, 835.
5. कपिला, उमा; इण्डियन इकोनॉमी सिन्स इण्डिपेन्डेंस,2002, पृष्ठ संख्या, 821,22.
6. अग्रवाल ए० एन०; भारतीय अर्थव्यवस्था", पृष्ठ संख्या,129.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com